



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 31 अगस्त, 2025

भाद्रपद 9, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 1470/छ:-पु०-9-2025 / 1933770

लखनऊ, 31 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प०आ०-201

सरकार की अधिसूचना संख्या 892/VI-P-9-2025-1933770 दिनांक 31 मई 2025 को अधिक्रमित करते हुए, उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2020 के नियम 10 सपठित उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2020) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषयक में निर्गत अन्य समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करके, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हैं या करने से छोड़ दी गयी हैं, श्री राज्यपाल यह प्रावधान करते हैं कि दावा अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की अवधि जो पांच वर्ष के लिये या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित है, को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार, 65 वर्ष की आयु के ऊपर अतिरिक्त 06 माह अथवा उक्त पद पर नवीन अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक विस्तारित किये जाने का उपबंध करते हैं और यह निर्देश देते हैं कि दावा अधिकरण के अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन पारिश्रमिक के साथ-साथ अवकाश तथा चिकित्सा उपचार और चिकित्सालय सुविधाएं तथा शक्तियां वहीं होंगी जैसी उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली नियम, 2020 में नियत की गयी है।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1470/VI-P-9-2025-1933770, dated August 31, 2025:

No. 1470/VI-P-9-2025-1933770

Dated Lucknow, August 31, 2025

IN exercise of the powers conferred by Rule 10 of the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Rules, 2020 *read* with Section 7 of the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020 (Uttar Pradesh Act no. 11 of 2020), and in supersession of all previous notifications issued on the subject except as respects things done or *omitted* to be done before such supersession, the Governor is pleased to make a provision that the tenure of the Chairman of the Claims Tribunal, originally fixed for a term of five years or until the attainment of sixty-five years of age, whichever is earlier, as per extant requirements, may be extended beyond the age of 65 years for a further period of six months or until the date of appointment of a new Chairman to the said post, whichever is earlier.

The Governor is further pleased to direct that the other terms and conditions of service of the Chairman of the Claims Tribunal, including salary, allowances, leave entitlements, medical treatment, hospital facilities, powers and functions shall be as prescribed in the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Rules, 2020.

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.